

मोदी-शी मुलाकात के बाद चीन का बदला सुर !

**ब्रिक्स के बीच राहुल-प्रियंका से मिले मलेशियाई
पीएम, ब्रेकफास्ट पर हुई मुलाकात**

भारतार्थ खबर
Bhaaraataarth.com

नई दिल्ली, 13 सितंबर 2026। नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात ने भारत-चीन संबंधों को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है। दोनों नेताओं की द्विपक्षीय बैठक के बाद चीन के सरकारी मीडिया में रिशतों को लेकर खयालातक संकेत दिखाई दिए हैं। चीनी सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने बैठक को दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। चीनी मीडिया के अनुसार, भारत और चीन के बीच पिछले कुछ समय में संबंधों को स्थिर करने की कोशिशों को अब आगे बढ़ाने का अवसर बना है। हालांकि, दोनों देशों के बीच सीमा और अन्य रणनीतिक मुद्दों पर मतभेद अभी भी मौजूद हैं। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि वास्तविक प्रगति का आकलन केवल शीर्ष स्तर की बैठकों से नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर होने वाले ठोस कदमों से किया जाना चाहिए। विश्वास निर्माण के नए चरण का दावा ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट में मोदी और शी जिनपिंग की नई दिल्ली में हुई बैठक को दोनों देशों के रिशतों में विश्वास निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाला बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों नेताओं के बीच

लगातार संवाद संबंधों में स्थिरता का संकेत है। चीनी मीडिया ने पिछले वर्षों में हुई शीर्ष स्तर की बैठकों का भी उल्लेख किया। उसके अनुसार, 2024 में कजान और 2025 में तियानजिन में



हुई मोदी-शी मुलाकातों के बाद अब नई दिल्ली की बैठक ने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए संवाद की निरंतरता कायम रखी है। रणनीतिक बातचीत को परिणाम में बदलने पर जोर पेंकिंग यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज से जुड़े विशेषज्ञ वांग शू ने ग्लोबल टाइम्स से बातचीत में बैठक के महत्व को रेखांकित किया। उनके अनुसार, कजान में हुई बातचीत

को संबंधों में महत्वपूर्ण मोड़, जबकि तियानजिन बैठक को संबंधों को पटरी पर लाने की दिशा में कदम माना जा सकता है। नई दिल्ली की बैठक को उन्होंने विश्वास को और मजबूत करने वाले चरण के रूप में पेश

किया। चीनी विशेषज्ञ के मुताबिक, अब दोनों देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती रणनीतिक सहमति को व्यावहारिक परिणामों में बदलने की है। शीर्ष नेताओं के बीच नियमित संवाद या गलत आकलन को संभावनाओं को कम करने में मदद मिल सकती है। सीमा से लेकर संपर्क तक कई मोर्चों पर बदलाव चीनी मीडिया की रिपोर्ट में भारत-चीन संबंधों में हाल के कुछ सकारात्मक घटनाक्रमों का भी

उल्लेख किया गया है। इनमें सीमा प्रबंधन से संबंधित समझ, सीमा व्यापार की बहाली, सीधी उड़ानों को दोबारा शुरू करने की दिशा में उठाए गए एकदम और दोनों देशों के लोगों के बीच सफेद कढ़ाई के प्रयास शामिल हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत और चीन जैसे दो बड़े देशों के बीच दीर्घकालिक विश्वास केवल राजनीतिक बयानों से कायम नहीं हो सकता। इसके लिए सीमा प्रबंधन की व्यवस्थाओं को मजबूत करना, व्यापार एवं निवेश से जुड़े व्यावहारिक मुद्दों पर प्रगति करना और लोगों के बीच सफेद कढ़ाई बढ़ाना जरूरी होगा। BRICS, SCO और G20 में सहयोग की संभावना ग्लोबल टाइम्स ने भारत और चीन के बीच सहयोग के लिए बहुपक्षीय मंचों को भी महत्वपूर्ण बताया है। ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन और G20 जैसे मंच पर दोनों देश वैश्विक शासन व्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, विकास वित्त और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर साझा हितों के आधार पर सहयोग बढ़ा सकते हैं। चीन के विशेषज्ञों के अनुसार, यदि दोनों देशों के बीच व्यावहारिक सहयोग का दायरा बढ़ता है तो इससे पुराने मतभेदों का प्रभाव कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, सहयोग

की यह प्रक्रिया सीमा विवाद और
 राजनीतिक प्रतिस्पर्धा जैसे संवादशील मुद्दों
 से अलग नहीं है। इसलिए संबंधों को पूरी
 तरह सामान्य बनाने की राह में कई
 चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। आगे की
 राह में चुनौती भी, संभावना भी मोदी-शां
 जिनपिंग की मुलाकात और उसके बाद
 चीनी सरकारी मीडिया में आई सकारात्मक
 टिप्पणियों को भारत-चीन संबंधों में संवाद
 की निरंतरता के संकेत के तौर पर देखा जा
 सकता है। लेकिन इसे दोनों देशों के बीच
 सीमा विवादों के समाधान के रूप में देखना
 अभी जल्दबाजी होगी। भारत और चीन के
 रिश्ते व्यापार, सीमा सुरक्षा, क्षेत्रीय
 राजनीति और वैश्विक मंचों पर सहयोग
 जैसे कई आयामों से जुड़े हैं। ऐसे में आने
 वाले समय में सीमा पर स्थिरता, आर्थिक
 संबंधों में प्रगति और उच्चस्तरीय संवाद की
 निरंतरता यह तय करेगी कि दोनों देशों के
 बीच हालिया सकारात्मक माहौल किस हद
 तक स्थायी सुधार में बदलता है। पिछला
 इतना जरूर है कि नई दिल्ली में हुई मोदी-
 शांजिनपिंग की मुलाकात के बाद चीन के सरकारी
 मीडिया का बदला हुआ सकारात्मक स्वर
 भारत-चीन संबंधों की दिशा पर नई नजर
 डालने का आश्वासन है।

भारतार्थ खबर
BhaaratAarth.com
नई दिल्ली, 13 सितंबर 2026।
मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने नई दिल्ली में कांग्रेस सांसद एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात ब्रेकफास्ट के दौरान हुई। मुलाकात की तस्वीरों भी सामने आई हैं, जिनमें नेता आरुप में बातचीत करते नजर आ रहे हैं। यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत की यात्रा पर हैं। भारत की मेजबानी में 12 और 13 सितंबर को आयोजित हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन में मलेशिया साझेदार देश के रूप में शामिल हुआ है। राहुल गांधी को बताया था पारिवारिक मित्र राहुल गांधी और अनवर इब्राहिम के बीच पहले भी मुलाकात हो चुकी है। वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत यात्रा के दौरान अनवर इब्राहिम ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी। उस समय एक न्यूज चैनल से बातचीत में मलेशियाई प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी के साथ

हुई मुलाकात को सकारात्मक बताते हुए उन्हें पारिवारिक मित्र बताया था। उन्होंने यह भी कहा था कि सभी पक्षों के साथ संवाद बनाए रखना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी से भी द्विपक्षीय वार्ता भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र

किनाबालु में भारत का वाणिज्य दूतावास
खोलने के लिए मलेशिया की सहमति व
जानकारी भी दी। ब्रिक्स सम्मेलन के बी
बढ़ी कूटनीतिक सक्रियता मलेशिया
प्रधानमंत्री 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन
भाग लेने के लिए शुक्रवार को नई दिल्ली

पहुँचे। उनकी भारत यात्रा को दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ हुई ब्रेकफास्ट मुलाकात ने भी राजनीतिक और

मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक भी की। विदेश मंत्रालय के अनुसार, दोनों नेताओं ने भारत और मलेशिया के बीच व्यापार एवं निवेश, रक्षा और सुरक्षा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, सीमांकित कटर, बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, फिनटेक, शिक्षा, पर्यटन और लोगों के बीच संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। बैठक में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने सबाह के कोट

आकाशपति किया है। हालांकि, उपरोक्त जानकारी के अनुसार इस अनौपचारिक मुलाकात में किन विशिष्ट मुद्दों पर चर्चा हुई, इसका आधिकारिक विवरण सामने नहीं आया है। केरल भी जाएंगे अन्तर्द्विब्राह्मण भारत यात्रा के दौरान मलेशिया प्रधानमंत्री के केरल जाने का भी कार्यक्रम है, जहां वे भारत के ग्रेड्ड मुफ्त से मुलाकात करेंगे। उनकी यात्रा आधिकारिक बैठकों के साथ विभिन्न स्तरों पर संपर्क और संवाद भी शामिल है।

BRICS में मोदी के सामने भारत ने खींचा ध्यान

भारतार्थ खबर
Bhaaratarth.com

नई दिल्ली, 13 सितंबर 2026। नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखे गए देश के नाम वाले प्लोकार्ड ने खासा ध्यान आकर्षित किया। इस प्लोकार्ड पर INDIA के बजाय BHARAT लिखा दिखाई दिया। अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश के नाम के इस स्वरूप ने एक बार फिर भारत और इंडिया दोनों नामों के संवैधानिक एवं आधिकारिक इस्तेमाल को लेकर चर्चा को जन्म दिया है। भारत इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स देशों के नेता वैश्विक आर्थिक सहयोग, व्यापार, सतत विकास और बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों सहित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखी गयी भारत नाम

वाला प्लेकार्ड चर्चा का विषय बन गया। संविधान में दोनों नामों को मान्यता भारत के संविधान में देश के



नाम को लेकर स्पष्ट प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 1 में देश का उल्लेख “India, that is Bharat” के रूप में किया गया है।

इसका अर्थ है कि इंडिया और भारत दोनों ही देश के संवैधानिक रूप से मान्य नाम हैं। इसलिए अंतरराष्ट्रीय बैठकों या

आधिकारिक आयोजनों में भारत नाम का इस्तेमाल संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप है। हालांकि अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में देश के नाम के लिए India

अथवा Bharat का इस्तेमाल देखने को मिलता रहा है। G20 में भी दिखा था भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भारत नाम का इस्तेमाल पहली बार नहीं हुआ है। वर्ष 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भी प्रधानमंत्री के सामने रखे गए प्लेकार्ड पर भारत लिखा गया था। उस समय देश के नाम के आधिकारिक इस्तेमाल को लेकर राजनीतिक बहस तेज थी। विपक्षी दलों ने इसे उस समय बने INDIA गठबंधन के राजनीतिक संदेश से जोड़कर सवाल उठाए थे। हालांकि संवैधानिक तौर पर देश के दोनों नाम मान्य होने के कारण केवल भारत लिखे जाने से देश के नाम में कोई कानूनी बदलाव नहीं होता। INDIA गठबंधन के बाद तेज हुई थी बहस जुलाई 2023 में कई विपक्षी दलों ने मिलकर Indian National Developmental Inclusive

Alliance (INDIA) नामक गठबंधन बनाया था। इसके बाद सितंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री के सामने भारत नाम वाले प्लेकार्ड में राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया था। उस समय विश्वी श्लोकों की ओर से आरोप लगाए गए थे कि भारत नाम के इस्तेमाल को INDIA गठबंधन के राजनीतिक संदर्भ से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं, देश का नाम बदलकर केवल भारत किए जाने की अटकलें भी राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनी थीं। हालांकि संवैधानिक स्थिति स्पष्ट है कि देश के लिए इंडिया और भारत दोनों नाम मान्य हैं। इसलिए किसी एक नाम के इस्तेमाल को अपने आप में संवैधानिक बदलाव नहीं माना जा सकता। BRICS में भारत के इस्तेमाल का संदेश ब्रिक्स जैसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रधानमंत्री के सामने भारत नाम का प्लेकार्ड दिखाई देना

निश्चित रूप से प्रतीकात्मक महत्व रखता है। हालाँकि इसके पीछे किसी विशेष राजनीतिक या कूटनीतिक निर्णय का संकेत है, ऐसा कहने के लिए फिलहाल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इसलिए इसे देश के संवैधानिक रूप से मान्य नाम भारत के आधिकारिक इस्तेमाल के रूप में देखना अधिक उपयुक्त होगा। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर दोनों नामों का प्रयोग परिस्थितियों और आयोजन की आधिकारिक व्यवस्था के अनुसार होता रहा है। इम्फ़रर सम्मेलन में भारत नाम के इस इस्तेमाल ने एक बार फिर यह याद दिलाया है कि देश की संवैधानिक पहचान में भारत और इंडिया दोनों ही नाम समान रूप से मान्य हैं। आने वाले अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में किस नाम का इस्तेमाल किया जाता है, इस पर भी राजनीतिक और सार्वजनिक चर्चा जारी रहने की संभावना है।

भारतार्थ खबर
Bhaaraataarth.com
नई दिल्ली, 13 सितंबर 2026।
दिल्ली के स्वरूप नगर हलाके में रविवार को एक फैक्ट्री एवं गोदाम में भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। हादसे में छह लोगों के घायल होने की सूचना है। घटना की जानकारी मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस की टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए

हुई। घटना के बाद पुलिस और दमकल विभाग की टीमों ने आसपास के क्षेत्र व सुरक्षित बनाने तथा आग के प्रभाव व नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई की। दमकल टीम ने संभाला मोर्चा आग व सूचना मिलने के बाद दिल्ली फायर सर्विस की टीमों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। दमकल अधिकारियों ने निर्देश पर आग बुझाने का अभियान

ब्रिक्स घोषणापत्र में भारत की कूटनीतिक बढ़त, टैरिफ से आतंकवाद तक अहम सहमति



भारतीय खबर Bharataarth.com
नई दिल्ली, 13 सितंबर 2026 | नई दिल्ली में आगेजित विधन क्रिस्वा शिखर समेत के दौरान सदस्य देशों के बीच 18 वीं वियुक्त प्रश्नों पर मतभेद के बाद नूतन नई दिल्ली घोषणापत्र पर सहमति बन गई। दो दिवसीय सम्मेलन के पहले सत्र के बाद जारी इस घोषणापत्र में आतंकवाद, वैश्विक व्यापार, प्रथम प्रणिया के स्थिति, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा और विकासशील देशों की भूमिका सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर सझा रुख सामने आया है। भारत की अचर्यवादी में ह्युर सम्मेलन में घोषणापत्र को अंतिम रूप देने के लिए सदस्य देशों के बीच लंबी कूटीनीतिक बातचीत चली। खालतौर पर प्रथम प्रणिया के स्थिति को लेजर भाषा पर सहमति बनाया नूतनीपूर्ण छ। अंततः सत्र सदस्य देशों की सहमति के बाद घोषणापत्र को स्वीकार किया गया। 140 बिंदुओं वाले घोषणापत्र पर वनी सहमति नई दिल्ली घोषणापत्र कनेव 45 प्रुषों का है और इसमें लगभग 140 बिंदुओं पर सदस्य देशों की सहमति दर्ज की गई है। रिपोर्ट अनुसार, सदावाजे के अधिष्ठास हिरसे पर पहले ही सहमति बन चुकी थी, लेकिन प्रथम प्रणिया के कनेटाग्रम को लेजर शब्दों के चमन पर अंतिम दैतर बन बातचीत जारी छी। भारत ने सदस्य देशों के बीच संवाद और सहमति बनाने के लिए सझित कूटीनीतिक प्रयास किए। रूख, चीन और अन्य सदस्य देशों के साथ लगातार बातचीत के बाद संयुक्त महीने पर सहमति बनी और घोषणापत्र को अंतिम रूप दिया गया। एकातरसत वैरुस और व्यापार प्रतिक्रियों के

किता व्यापार के मोचे पर क्रिसमा देसों ने एकतरफ
 रैफैण और व्यापारप्रतिबंधों को लेकर किता व्यक्त
 की। घोषणापत्र में स्पेस व्यापारिक उपायों के प्रति
 असहमति जताई गई है, जिन्हें विमरशनीय
 देसों के लिए भेकबावपूर्ण न, संरक्षणवादी माना
 जा सकता है। यूरोपीय संघ के कार्वन बॉर्डर
 एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) का भी
 स्पष्ट उल्लेख किया गया है। क्रिसमा ने जलवायु
 संबंधी व्यापार उपायों के नाम पर विमरशनीय
 अर्थव्यवस्थाओं के लिए 'नई व्यापारिक बाधाएं'
 खड़े किए जाने की आशंका पर किता जताई।
 साथ ही विकास पर संयुक्त नई व्यापार सुधार
 की आवश्यकता दोहराई गई है। क्रिसमा देसों
 ने ऐसी वैश्विक व्यापार व्यवस्था की सलाह
 बताई, जिसमें उपभोक्ता और विकासशील
 अर्थव्यवस्थाओं की भागीदारी और प्रभाव
 बढ़े। पहलवान आतंकी हमले की स्पष्ट निंदा
 आतंकवाद के मुद्दे पर घोषणापत्र में भाषा के लिए
 महत्वपूर्ण संदेश सामने आया। क्रिसमा ने
 26 दिसंबर 2025 को जम्मू-कश्मीर के
 पहलगाम में हुए आतंकी हमले की स्पष्ट और
 कड़े शब्दों में निंदा की। इस हमले में 26 लोगों
 की मौत हुई थी। घोषणापत्र में आतंकवाद के
 सभी रूपों से मुकाबले की प्रतिबद्धता दोहराते
 हुए आतंकवाद के विरोधीपक्ष के नेतृत्व को

गया करके, आदिवासी की सीमा पर आवाजाने से करने और आत्मरक्षादी संघर्षों को सुविधित्वा दिक्कने जलस्थित नही करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। साथ ही आत्मरक्षा को किसी धर्म, गुणवत्ता या सभ्यता से जोड़ने से बचने और आत्मरक्षा गतिविधियों में शामिल लोगों को कमजोर के तहत जवाबदेह ठहराने की बात कही गई है। पश्चिम एशिया में संस्य और संघर्ष की अपील ब्रिक्स घोषणापत्र में पश्चिम एशिया की मौजूद स्थिति पर की गंधीर चिंता जताई गई। सदस्य देशों में संबंधित गंधी से अतिव्यवस्य समन बताने और तनाव को से बचने की अपील की, जिन्से क्षेत्रीय और पाला करों बढ सकता है। नागरिकों तथा नागरिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा, देशों की संरुंधा और क्षेत्रीय अखंडता के समाना तथा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया गया। परमाणु जोखिम को कम करने और बायोचिंता एवं कृषिचिंता के माध्यम से स्थानीय समाधान खोजने की आवश्यकता की रेखांकित की गई। फरस्तलीन मुद्दे पर विस्तृत रुख घोषणापत्र में फरस्तलीन के मुद्दे को भी प्रसुता देाई है। गाजा में जारी हिंसा और फलस्तलीनियों के जबर्न विस्थापन को लेकर चिंता व्यक्त की गई। ब्रिक्स ने 1967 की सीमाओं के आधार पर पूर्वी येरुशलम को राजधानी बनाकर एवं सूचनित एवं संप्रभु फलस्तलीन राष्ट्र की स्थापना के समर्थन को दोहराया। साथ ही संयुक्त राष्ट्र में फलस्तलीन की पूर्ण सदस्यता और अंतराराष्ट्रीय संस्थाओं में उसके उचित प्रतिनिधित्व की बात कही गई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्ष और भारत की भूमिम ब्रिक्स नेताओं से संयुक्त सुरक्ष और विसेश रूप से सुरक्ष राष्ट्र सुरक्षा पसिद में सुरक्ष की आवश्यकता पर पसिद जोर दिया। लक्ष्य सुरक्षा पसिद को वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के अनुस्य अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण, प्रभावी और लोकतांत्रिक बनाना बतावा गया। घोषणापत्र में भारत और ब्राजील की बड़े भूमिम निधानों की आवश्यकता के समर्थन को उल्लेख की महत्वपूर्ण है।

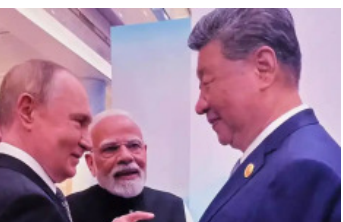
भारतार्थ खबर
Bhaaratarth.com

नई दिल्ली, 13 सितंबर 2026 | नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी को लेकर महत्वपूर्ण कूटनीतिक संदेश सामने आया है। ब्रिक्स के नई दिल्ली घोषणापत्र में संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधारों की आवश्यकता पर जोर देते हुए विकासशील देशों की भागीदारी बढ़ाने की बात कही गई है। चीन और रूस ने संयुक्त राष्ट्र में भारत तथा ब्राजील की बढ़ती भूमिका की आकांक्षाओं के प्रति अपना समर्थन देरहवा है। भारत के लिए यह घटनाक्रम इसपरि महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि चीन और रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों में शामिल हैं और दोनों के पास वीटो अधिकार है। ऐसे में भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की दावेदारी के संदर्भ में उनका समर्थन कूटनीतिक रूप से अहम माना जाता है। सुरक्षा परिषद में सुधार पर जोर नई दिल्ली घोषणापत्र में ब्रिक्स देशों ने संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था में व्यापक सुधार की आवश्यकता रेखांकित की है। घोषणापत्र के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण, प्रभावी और लोकतांत्रिक बनाने की दिशा में सुधार जरूरी है। ब्रिक्स नेताओं ने विकासशील देशों और ग्लोबल साउथ की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया। भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के विस्तार और विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व दिए जाने की मांग करता रहा है। चीन और रूस के

मैं भारत की दावेदारी

रूस का समर्थन

रुख का महत्व भारत की दावेदारी के संदर्भ में चीन और रूस का समर्थन विशेष महत्व रखता है। दोनों देश सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होने के कारण किसी भी बड़े सुधार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ब्रिक्स घोषणापत्र में वर्ष 2023 के जोहानिसबर्ग शिखर सम्मेलन में व्यक्त विचारों का भी उल्लेख किया गया है। इसमें चीन और रूस



की ओर से समुक्त राष्ट्र में भारत की बड़ी भूमिका निभाने की आकांक्षा के प्रति समर्थन देहरादू जाने की बात सामने आई है। हालाँकि, मुख्य परिषद में सुचारु और नए स्थायी सदस्यों को शामिल करने की प्रक्रिया व्यापक औरंतराष्ट्रीय सहमति पर निर्भर करती है। इसलिए क्रिसमस पर यह संकेत को भारत की स्थायी सदस्यता का अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता। शी जिनपिंग की भारत यात्रा भी रही चर्चा में क्रिसमस सम्मेलन के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा भी प्रमुख कूटनीतिक घटनाक्रम रही। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मौजूदगी ने वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित किया। सम्मेलन के दौरान तीनों नेताओं के बीच सीहार्दयपूर्ण दृश्य भी देखने को मिले। इसके साथ ही नई दिल्ली घोषणापत्र पर सहमति ने बहुपक्षीय मंचों पर भारत-चीन-रूस के बीच संवाद की संभावनाओं को लेकर चर्चा बढ़ाई। पहलगीम हमले का उल्लेख भी महत्वपूर्ण नई दिल्ली

घोषणापत्र में आतंकवाद से जुड़े मुद्दों को लेकर व्यक्त किए गए रुख ने भी स्थान अर्थात् प्राप्त किया है। भारत के लिए यह रुख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह लगातार सीमा पर आतंकवाद और आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्पष्ट कार्रवाई की मांग करता रहा है। चीन की ओर से घोषणापत्र में भारत के रुख के अनुरूप किसी मुद्दे का समर्थन किए जाने को भारत-चीन संबंधों के व्यापक संदर्भ में देखना जा रहा है। हालाँकि, इसे दोनों देशों के बीच सशस्त्र रणनीति मतभेदों के समाप्त होने का संकेत मानना उचित नहीं होगा। पाकिस्तान के लिए बदला क्षेत्रीय समीकरण ब्रिक्स घोषणापत्र और भारत की UNSC दवेदारी को लेकर चीन की संधर्भ नै पाकिस्तान की कूटनीतिक विताओं को बढेने की संभावना जताई जा रही है। पाकिस्तान लवे समय से भारत की वैश्विक संस्थाओं में बढती भूमिका को लेकर आपत्ति जताता रहा है। भारत को यदि सुझा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए व्यापक अंतरराष्ट्रीय समर्थन मिलता है, तो इससे वैश्विक मंचों पर उसकी कूटनीतिक स्थिति और मजबूत हो सकती है। हालाँकि, सुझा परिषद के विस्तार का मुद्दा अभी भी जटिल अंतरराष्ट्रीय वाताओं और सदस्य देशों की सहमति से जुड़ा हुआ है। भारत की कूटनीतिक रणनीति के लिए अहम संकेत नई दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र धुधार, स्लोबल साउथ की भागीदारी और भारत की बढी भूमिका को लेकर सामने आए संकेत भारतीय कूटनीति के लिए महत्वपूर्ण हैं। चीन और रूस जैसे स्थायी सदस्यों का समर्थन भारत की दवेदारी को रणनीतिक वजन जरूर देता है।

दमकल की करीब 15 गाड़ियों को लगाया गया। पुलिस के अनुसार आग स्वरूप नगर की गली नंबर-2 स्थित खसरा नंबर 357/58 की एक इमारत में लगी। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक इमारत के बेसमेंट और पहली मंजिल में एक कच्ची संचालित हो रही थी, जबकि दूसरी मंजिल पर टिन की शेड बनी हुई थी। लगभग 200 वर्ग गज क्षेत्र में स्थित इस परिसर में रेक्सिन की कतरन और सूती बुनाई से संबंधित सामग्री का गोदाम भी बताया गया है। बताया गया कि यहाँ जुड़ो के कपड़े और मुक्केबाजी के दस्ताने तैयार किए जाते थे। आग लगने के बाद परिसर से धुआँ तेजी से फैलने लगा, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। इसी दौरान सामने वाली इमारत के कुछ लोगों ने घबराकर बाहर निकलने का प्रयास किया। धुएँ से पांच लोग प्रभावित, एक को गिरने से चोट पुलिस के मुताबिक हादसे में आसपास के घर में रहने वाले छह लोग घायल हुए। इनमें पांच लोगों को बाबू जगजीवन राम अस्पताल तथा एक घायल को बुवाई स्थित सरकारी अस्पताल ले जाया गया। बताया गया कि एक व्यक्ति पास की इमारत से नीचे कूद गया, जिससे उसके दाहिने पैर में चोट आई। अस्पताल ले जाए गए पाँच घायलों की हालत खतरा से बाहर बताई गई है। घायलों में अधिकांश को धुएँ के कारण सांस लेने में परेशानी

चलाया गया। अधिकारियों के अनुसार आग पर नियंत्रण पाने के लिए पर्याप्त संख्या में दमकल वाहन तैनात किए गए। दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आग फैकट्री परिसर में रखे ज्वलनशील सामग्री तक फैल गई थी। विधिवस की कतम और अन्य सामग्रियों के कारण आग बुझाने के दौरान विशेष सावधानी बरतनी पड़ी। आग लगने के कारणों की जांच जारी फिलहाल आपदा प्रकरणों के वास्तविक कारणों का स्पष्ट स्वरूप से पता नहीं चल पाया है। दिल्ली पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और आग के कारणों का पता लगाने के साथ-साथ फैकट्री परिसर में सुरक्षा प्रणालियों की स्थिति की भी जांच की जा रही है। पुलिस और दमकल विभाग वाहन और से घटनास्थल से संबंधित तथ्यों को जुटाया जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद आग लगने के कारण और घटना के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों के बारे में अधिक जानकारी सामने आने की संभावना है। स्थानीय स्तर पर घटना ने औद्योगिक एवं गोदाय क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे परिसरों में ज्वलनशील सामग्रियों के भंडारण, आपातकालीन निकास और अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता जैसे-जैसे आग का नियंत्रित निरीक्षण बेहतर आवश्यक है।

